सूरसागर में कई घरों की छतों पर पत्थरों के ढेर नज़र आए

ड्रोन कैमरे से हुए सर्च ऑपरेशन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

- विशेष स्पैशल टास्क फोर्स दस्ता भेजकर छतों से पत्थर हटाए गए। कुल दो ट्रॉली भरकर पत्थर निकले।
- पुलिस ने आशंका जताई कि, यह माहौल बिगाड़ने की साजिश का अंग है। इसके लिए मकान मालिकों से सख्त पूछताछ की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि, सूरसागर क्षेत्र में ईदगाह की दीवार से गेट निकालने को लेकर क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो गया था। इस दौरान एक दुकान जला दी गई, पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें दो पुलिस अफसर घायल हो गए।
- पुलिस की सख्ती के बाद से फिलहाल तो माहौल शांत है तथा सूरसागर, प्रताप नगर, देव नगर व राजीव गांधी नगर, थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू है।

जोधपुर, 24 जून (कासं)। जोधपुर के सूरसागर में उपद्रव के बाद पुलिस ने सूरसागर इलाके की तलाशी में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यहां कई घरों की छत पर पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। ड्रोन कैमरे में ये सब नजर आने के बाद पुलिस ने एस.टी.एफ. टीम को फौरन इन घरों की छत पर भेजा और यहां से 2 ट्रॉली से ज्यादा पत्थर बरामद किए। अब पुलिस इन मकान मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

पुलिस को आशंका है कि यहां छतों पर जमा किए गए पत्थरों से एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। इसी के चलते रविवार को इस इलाके में ड्रोन सर्वे करवाया गया था। आधा दर्जन से ज्यादा घरों की छत पर पत्थरों का ढेर देखा गया। पुलिस ने सभी संबंधित मकान मालिकों के नाम-पते नोट कर लिए। अब जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

उपद्रव के आरोप में 67 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है। अब तक 43 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। उपद्रव के तीसरे दिन रविवार को सूरसागर इलाके का पूरा बाजार बंद रहा। ओमवार को क्षेत्र में शांति रही।

रविवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई न की जाए। लेकिन दोषियों को बख्शा न जाए। प्रतिनिधिमंडल में भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे करण सिंह उचियारड़ा और जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा शामिल थे।

गौरतलब है कि सूरसागर थाना इलाके की राजाराम सर्किल स्थित ईदगाह के मुख्य गेट के पास कुछ दुकानें हैं। गुरुवार को गेट निकालने का काम शुरू किया गया था। बस्ती में रहने वाले कुछ लोग गेट निकालने का विरोध कर रहे थे। दो दिन में दो बार दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका था। पुलिस ने मामला शांत करवा दिया था।

इसके बाद शुक्रवार को फिर गेट निकालने की कोशिश हुई तो बस्ती के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। वे गेट निकालने के काम को बंद करने की बात पर अड़ गए थे। तब दूसरे पक्ष के लोग भी वहां आ गए और गेट बनाने के लिए अड़े रहे। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए थे।

शुक्रवार रात को हुए उपद्रव में लोग छतों से पथराव कर रहे थे। इसमें 16 पुलिसकर्मी फंस गए थे। दो बार पुलिस के जवान पीछे हटे। उपद्रवियों ने एक दुकान में आग भी लगा दी थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब तीन घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। पथराव में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना के थानाधिकारी नितिन दवे और शास्त्री नगर थाना के सब इंस्पेक्टर शैतान सिंह भी घायल हुए थे।

जोधपुर वेस्ट डीसीपी राजेश कुमार यादव ने बताया कि लोकल एरिया में तो हम ऐसे उपद्रवियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो भी दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है।

सूरसागर में दो पक्षों में विवाद के बाद सूरसागर, प्रतापनगर, देवनगर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में अभी भी धारा 144 लगी हुई है। सूरसागर क्षेत्र में जहां विवाद हुआ था, वहां पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस दर्ज मामलों में जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र में अब शांति है।

राज्यसभा में सदन के नेता की जिम्मेदारी संभालेंगे जे.पी. नड्डा

नई दिल्ली, 24 जून। राज्यसभा में जे.पी. नड्डा नेता सदन की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। उनसे पहले पीयूष गोयल राज्यसभा के नेता थे, जो इस बार मुंबई की एक सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। ऐसे में राज्यसभा में सबसे वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ही थे, जिन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। चर्चा है कि उन्हें जल्दी ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जा सकता है और उनके उत्तराधिकारी की पार्टी ने तलाश तेज कर दी है। अगले कुछ महीनों में ही भाजपा नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है।

- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है।

भाजपा में आमतौर पर एक व्यक्ति, एक पद की नीति रही है। ऐसे में कयास तेज हैं कि जेपी नड्डा की जगह अब भाजपा किसी और नेता को ही पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगी। उनके विकल्प के तौर पर विनोद तावड़े, सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। फिलहाल हरियाणा, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों ही चुनाव होने हैं। ऐसे में यह भी चर्चा है कि भाजपा की ओर से कुछ दिनों के लिए जेपी नड्डा और सेवा विस्तार मिल सकता है। उस अवधि में उनको कामकाज में मदद करने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष दिया जा सकता है।

राजस्थान को 2 रीज़नल पूल से बिजली मिलेगी

जयपुर, 24 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान को 2 रीजनल पूल से अनावंटित बिजली का कोटा देने निर्णय किया है। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है, 400 मेगावाट) बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है।

इस अनावंटित बिजली की आपूर्ति 26 जून से प्रारंभ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन एवं बिजली की आपूर्ति के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

- मु.मंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान को अनावंटित बिजली देने की मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली यात्रा के दौरान ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस बारे में मुलाकात की थी।
- केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान को दो अनावंटित पूल से कुल 400 मेगावॉट बिजली 24 घंटे दी जाएगी।

जैसा कि विदित है कि, मुख्यमंत्री शर्मा ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से हाल ही में नई दिल्ली में मुलाकात की थी। जिसके बाद केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 24 जून, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पत्र लिखकर राजस्थान को दक्षिण एवं पश्चिम रीजन के अनावंटित पूल से 200-200 मेगावाट (कुल

गत दिनों राजस्थान को छत्तीसगढ़ में फंसे 4 लाख मीट्रिक टन (लगभग 100 रैक्स) कोयले की आपूर्ति का निर्णय भी हुआ था। इस कोयले से प्रदेश के पावर प्लांट्स में कोयले के भंडार बढ़ेंगे और आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

इमर्जेंसी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं बल्कि पार्टी के मुख्यालयों तक सीमित है। यह अवधि कांग्रेस की एकतरफा तानाशाही का पर्याय बन गई थी, इस दौरान नागरिकों के सभी नागरिक अधिकार खत्म हो गए थे और असहमति की आवाज़ों को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया था। बलूनी ने यह भी कहा था कि, आज भी इस काले दिन के पाठ को जब भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो 25 जून 1975 की दिल को भयभीत करने वाली गहरी यादें पुनः याद आ जाती है।

एक प्रैस विज्ञप्ति में, उन्होंने कहा कि इस आपातकाल की घटना के विरोध में 25 जून को दिन 12:30 बजे भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के दिल्ली केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि यह विरोध प्रदर्शन यह बताने के लिए है कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा था, नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था, 21 महीनों तक विपक्ष के नेताओं पर अत्याचार किए गए थे तथा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) व भारतीय रक्षा नियम (डी.आई.आर.) के तहत मीडिया को कुचला गया। सत्य बोलने वालों की आवाज़ दबा दी गई, भारत की लोकतांत्रिक अखंडता को कमज़ोर किया गया व जनता का दमन किया गया था।

"ब्रिटानिया"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फैक्टरी का प्रोडक्शन बंद रहेगा। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि, फैक्टरी का बंद होना वास्तव में बंगाल के पतन का प्रतीक है, एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था वह आज अव्यवस्था की वजह से पतन के रास्ते पर है।

तारातल प्लांट ब्रिटेनिया की सबसे पुरानी फैक्ट्रियों में से एक है। यह पिछले 7 दशक से लगातार उत्पादन कर रही है। जबकि अभी पिछले 20 दिनों से कंपनी का प्रोडक्शन बंद है। कंपनी के मार्केटिंग एवं बिजनेस लीडर गौतम राय ने कहा कि, कंपनी ने अभी तक बंद को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है।

ब्रिटेनिया मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के बाकी बचे 5 साल 11 महीने के कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपये देने का वादा किया है। जिस भी कर्मचारी की नौकरी अभी 6 से 10 साल तक बाकी है उसे 18.5 लाख रुपय, 10साल से ज्यादा बाकी कार्यकाल वाले कर्मचारी को 22.25 लाख रुपय देने का वादा किया है।

मालवीय ने फैक्ट्री बंद होने का ठीकरा सीपीआईएम की यूनियनबाजी और टी.एम.सी. की तौलाबाजी पर फोड़ा। भाजपा के एक नेता ने कहा कि ब्रिटानिया फैक्ट्री जो कभी बंगाल में औद्योगिक जीवन शक्ति का प्रतीक थी, उसे पहले सीपीआईएम की यूनियनबाजी और फिर बाद में टीएमसी की अथक तौलाबाजी का सामना करना पड़ा। टीएमसी की तौलाबाजी फैक्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मालवीय ने कहा कि इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद प्रदेश में रोजगार की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अधिकतम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खुदरा विक्रेता इस दौरान अपने पास 10 टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकेंगे। थोक विक्रेताओं और स्टॉक सीमा व्यापारियों के लिए अधिकतम स्टॉक की सीमा तीन हजार टन रखी गयी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू करने का यह आदेश विनिर्दिष्ट खाद्य उद्य उत्पादों पर लाइसेंसिंग शर्त, स्टॉक सीमा और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधित करने) के आदेश, 2024 को आज यानी 24 जून से तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इसी तरह आटा मिलें चालू वित्त वर्ष के बाकी माह की संख्या के गुणक के आधार पर अपनी मासिक प्रसंस्करण क्षमता के 70 प्रतिशत के हिसाब से गेहूं स्टाक रख सकती हैं।

हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट के बीच उठापटक की राजनीति तेज हुई

इंडियन नैशनल लोक दल के प्रमुख अभय चौटाला ने भी हुड्डा पर लोकसभा चुनाव में भाजपा से सांठगांठ करने का आरोप लगाया

चंडीगढ़, 24 जून। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि उसकी उम्मीदें कम से कम 7 या 8 सीटें हासिल करने की थीं। अब इसे लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस में भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के दो गुट माने जाते हैं। अकसर कुमारी शैलजा मुखर रही हैं और हुड्डा को निशाने पर लेती रही हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से इशारों में ही हुड्डा खेमे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि टिकट बंटवारा सही से किया गया होता तो इंडिया अलायंस को हरियाणा में 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं।

कांग्रेस ने सूबे की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी। कुमारी शैलजा ने कहा कि, शायद हाईकमान या फिर राज्य के प्रभारी को जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास सही फीडबैक न पहुंचा हो। यदि ऐसा नहीं होता तो हम 5 की बजाय 8 या 10 लोकसभा सीट हासिल करते। कुमारी शैलजा ने अपने इस बयान में भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन टिकट बंटवारे का जिक्र कर हुड्डा कैम्प पर निशाना जरूर साध दिया। इसकी वजह यह है कि टिकट बंटवारे में कहा जाता है कि हुड्डा खेमे की ही चली है।

कुमारी शैलजा ने जहां पार्टी के भीतर से हुड्डा पर सवाल उठाया है तो वहीं इंडियन नैशनल लोक दल के प्रमुख नेता अभय चौटाला ने भी उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, हुड्डा ने भाजपा से सांठगांठ कर ली थी। इसके चलते ही कई सीटों पर कांठोस ने कमजोर उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने कहा कि हुड्डा अब भी भाजपा के हाथों खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव होने वाला है। इसके बाद भी हुड्डा अब तक तैयार नहीं हैं और विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारने से भाग रहे हैं। ऐसा तब है, जब विपक्ष इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रविवार को अंबाला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांठोस कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग तैयार रहें। असली लड़ाई तो अभी होनी है। उन्होंने कहा कि आपको यह तय करना होगा कि अंबाला की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करे।

हरियाणा में 23 हजार लोगों की सरकारी नौकरी छिन जायेगी?

- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली, 24 जून। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के बाद अब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। राज्य में सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है।

अब इस मामले में हरियाणा सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सरकार पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। अगर फिर भी राहत न मिली तो भर्तियां रद्द कर नए सिरे से एग्ज़ाम लेना ही सरकार के पास अंतिम रास्ता होगा। ऐसे में साल 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और और ग्रुप डी में नियुक्ति पा चुके 23 हजार युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है। अब उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। इन्हें भर्ती वाले साल में ही नियुक्ति भी दे दी गई थी।

हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा की नायाब सैनी सरकार सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मालूम हो कि, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। यह 5 मई, 2022 से लागू किया था।

इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की आमदनी सालाना 1.80 लाख रुपए से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदक को 5 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट में 1.80 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को बोनस अंक का लाभ दिया था। राज्य के परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को ही यह फायदा मिला। साल 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और डी की भर्ती में ये फैसला लागू हुआ था।

इंडिया और एन.डी.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रवंडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटें खाली हैं।

कांग्रेस की राजस्थान इकाई के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनाव के लिए चुनाव समितियों का गठन किया है। पार्टी के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की देखरेख चार सदस्यीय समिति करेगी, जिसे पार्टी के प्रचार समन्वय और रणनीति बनाने का काम सौंपा जाएगा। हाल में हुए आम चुनाव में मौजूदा विधायकों के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुईं 5 विधानसभा सीट झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा, खींवसर और चौरासी पर उपचुनाव होना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर बैठकों के लिए समितियों का गठन किया गया है ताकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दावा किया कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की विजय होगी। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की सभी 29 सीटों पर विजय हासिल की है। लोकसभा चुनाव के दौरान अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को 15 हजार मतों की बढ़त मिली थी। अब उपचुनाव में पार्टी 51 हजार से अधिक मतों से जीतेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राही ही पार्टी को जिताएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा में 332 बूथ हैं। लोकसभा चुनाव में लगभग 200 बूथों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता सजग प्रहरी बनकर अपने-अपने बूथ को और मजबूत बनाने, पार्टी के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आ ान किया कि वे सभी बूथों पर पार्टी को जिताने का संकल्प लेकर जाएं।

भाजपा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। नड्डा ने कहा इतना वीभत्स हादसा हुआ और आपके नेतृत्व वाली पार्टी इस पर चुप बैठी है। नड्डा ने आगे कहा कि कुछ मुद्दों के लिए हमें पार्टी से ऊपर उठकर आवाज उठानी चाहिए। एस.सी., एस.टी. का कल्याण व सुरक्षा ऐसे ही मुद्दे है।

नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर इसलिए भी निशाना साधा कि वे एक असफल नेता को स्थापित करने का प्रयास बार-बार कर रहे है।

उन्होंने कहा कि खड़गे जी आज वास्तव में "न्याय" की बात करने की जरुरत है। एक असफल नेता को स्थापित करने के लिए इसे नारे के रुप में प्रयुक्त ना करे। आज तमिलनाडू की जनता व समस्त एस.सी. समुदाय कांग्रेस, खासकर गांधी व इंडिया गठबंधन की दोहरी नीति देख रहा है।

भाजपा प्रमुख ने खड़गे से कहा कि वे राहुल और प्रियंका से कहे कि वे पीड़ितों से मिले या कम से कम उनके लिए आवाज तो उठाए।

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में अवैध शराब के धन्धे या शराब घोटाले की तरफ विशेष रुझान है।

संसद के पहले ही दिन प्र.मंत्री मोदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आवाज़ बुलंद करने देने की उनकी कोई योजना नहीं है।

प्रधानमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तीन गुना मेहनत करके तीन गुना परिणाम देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव महत्वपूर्ण थे, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद यह दूसरी सरकार है जिसे लगातार तीन बार राज करने के लिए चुना गया। उन्होंने मीडिया से कहा कि "यह अवसर 60 वर्ष बाद आया है। इसका मतलब है कि जनता ने उनकी सरकार के समर्पण, नीतियों और इरादों पर अपनी मुहर लगा दी है। मैं इसके लिए जनता को धन्यवाद अदा करता हूं।"

तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए "आपातकाल" का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "भारतीय लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे को कल 50 साल हो जाएंगे। नई पीढ़ी नहीं भूलेगी कि भारतीय संविधान को किस तरह से समाप्त किया गया, देश को किस तरह से एक जेल में तब्दील कर लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया। इस 50वीं बरसी पर देश एक शपथ लेगा कि ऐसा आगे कभी ना हो।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश और उसकी जनता की सेवा करने के लिए सबकों साथ लेकर चलने की निरंतर कोशिश करेगी, लेकिन साथ ही मैसेज भी देते हुए कहा कि "भारत को एक जिम्मेवार विपक्ष की जरुरत है, जनता अर्थपूर्ण बातें चाहती है, ना कि नारेबाजी।

वह बहस और कर्मठता चाहती है, ना कि संसद की कार्रवाई में व्यवधान। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा।"

उन्होने कहा कि देश का सांसदों से बहुत सी आकांक्षाए हैं। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे लोक कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएं। प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए ध्यान दिलाया कि यह पहला मौका है, जबकि नए सांसद नए संसद भवन में शपथ लेंगे।

कांग्रेस का निशाना बनाकर की गईं प्रधानमंत्री की टिप्पणियों और प्रहारों पर खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश यह उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नीट को लेकर हुए विरोध, पश्चिम बंगाल के ट्रेन हादसे या मणिपुर हिंसा के बारे में बोलेंगे। उन्होंने कहा कि, लोकसभा चुनावों में हुई नैतिक एवं राजनैतिक पराजय के बावजूद प्रधानमंत्री ने आज एक परम्परागत भाषण से अधिक लंबा भाषण दिया।

कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि "जनता यह उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के संदर्भ में युवाओं के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और महा-धांधली की कोई जिम्मेवारी नहीं ली। मोदी जी पश्चिम बंगाल में हाल ही हुए ट्रेन हादसे और रेलवे के कुप्रबंधन के बारे में भी चुप्पी साधे रहे। मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसाग्रस्त है, लेकिन मोदी जी ने वहाँ जाने की ज़हमत कभी नहीं उठाई ना ही उन्होंने वहाँ हुई ताज़ा हिंसा पर कोई चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि चाहे असम और नॉर्थ ईस्ट की बाढ़ हो, कमरतोड़ महंगाई हो, रूपए की ऐतिहासिक गिरावट या एग्ज़िट पोल-स्टॉक मार्केट के घोटाले का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री चुप हैं।

खड़गे ने कहा कि "मोदी सरकार ने जनगणना को काफी समय से लम्बित रखा हुआ है और प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना पर भी बिल्कुल खामोश हैं।"

कांग्रेस सांसदों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएं।

राहुल ने एन.डी.ए. सरकार के 10 नकारात्मक मुद्दे गिनाएं जिन्हें वे 15 दिनों में उठाएंगे, वे ये है:

1. पश्चिम बंगाल की ट्रेन दुर्घटना
2. कश्मीर में आतंकी हमला
3. रेल यात्रियों का बुरा हाल
4. नीट घोटाला
5. नीट पी.जी. रद्द
6. यू.जी.सी. नेट पेपर लीक घटना
7. दूध, दालें व गैस के दामों में वृद्धि
8. जंगलों में आग लगना
9. जल संकट चल रहा है
10. बचाव की कोई व्यवस्था नहीं होने से लू से हो रही मौतें

एन.डी.ए. के लिए नई चुनौतियाँ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंक शाखाओं की बहुत कम संख्या होने जैसे मुद्दे उठाएंगे।

पात्रा ने कहा, "कोयले की रॉयल्टी बढ़ाने की ओडीशा की मांग को पिछले दस सालों से केन्द्र ने नज़रअंदाज़ किया है। इससे राज्य की जनता को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि, उन्हें अपना उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।"

यह पूछे जाने पर कि, क्या बी.जे.डी. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देने के अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी, पात्रा ने कहा, "भाजपा को अब कोई समर्थन नहीं, केवल विरोध। हम ओडीशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "भाजपा को समर्थन देने का कोई प्रश्न नहीं है। बी.जे.डी. अध्यक्ष ने हमसे कहा है कि, यदि एन.डी.ए. सरकार ओडीशा की उचित मांगों को नज़र अंदाज़ करना जारी रखती है तो हम एन.डी.ए. सरकार के एक "सजीव व सशक्त विपक्ष के रुप में काम करें।"

ओडीशा विधानसभा चुनावों में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बी.जे.डी. ने सत्ता खो दी और भाजपा विजयी रही। लोकसभा चुनावों में भी बी.जे.डी. एक भी सीट नहीं जीत पाई। सन् 1997 में पार्टी के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।

पूर्व में बी.जे.डी. ने ना केवल संसद में भाजपा को मुख्य विधेयकों पर समर्थन दिया है, बल्कि 2019 और 2024 में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा में भेजने में भेजने में मदद भी की है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने, तीस्ता जल बंटवारा और फरक्का बैराज के पानी को लेकर बांग्लादेश के साथ हुई वार्ता में पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं करने पर "भारी एतराज़" जाहिर किया है।

बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि, पश्चिम बंगाल को शामिल किए बिना वे पड़ोसी देशों से ऐसी कोई वार्ता ना करें।

मोदी को लिखे, तीन पृष्ठों के अपने पत्र में उन्होंने कहा है, "मैं यह पत्र, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में लिख रही हूँ। ऐसा लगता है कि, गंगा और तीस्ता नदियों के जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर, उनके साथ मीटिंग के दौरान वार्ता हुई होगी। राज्य सरकार की सलाह तथा विचार लिए बिना किया गया एकतरफा विचार विमर्श व वार्ता ना तो स्वीकार्य है ना ही उचित है।"

उन्होंने कहा भौगोलिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक दृष्टि में बंगाल और बांग्लादेश में भारी समानता है।

बनर्जी ने कहा, "मैं बांग्लादेश के लोगों का भारी सम्मान करती हूँ उनसे प्रेम करती हूँ। लेकिन मैं इस बात पर अपनी गंभीर आपत्ति व्यक्त करती हूँ, बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे और फरक्का संधि सम्बंधी वार्ता राज्य सरकार को शामिल किए बिना नहीं होनी चाहिए थी।

पश्चिम बंगाल की जनता का हित सर्वोपरि है उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

ममता बनर्जी ने केन्द्रीय सरकार को...

- परम्परा के अनुसार, आज कोलकाता जो महसूस करता है वह कुछ समय बाद पूरा बंगाल महसूस करता है। वामपंथी सरकार पहले कोलकाता के म्युनिसिपल क्षेत्रों में हारने लगी, देखते-देखते ही, कुछ समय में बंगाल की गद्दी उसके हाथ से निकल गई।
- यह इतिहास जानते हुए, ममता बनर्जी का भयभीत होना, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यापक भ्रष्टाार का कोई स्कोप नहीं होता था। वर्ष 2017 तक मैडिकल के एन्ट्रेन्स एग्ज़ाम राज्य सरकारों के अधीन ही होते थे।

बनर्जी ने ध्यान दिलाया कि राज्य मैडिकल डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पर 50 लाख रूपए खर्च करते हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया में भी उन्हें अहमियत देनी चाहिए। मैडिकल एन्ट्रेन्स परीक्षाओं के केन्द्रीकरण का परिणाम सहयोगात्मक संघवाद के सीमित होने के रूप में हुआ।

लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ममता बेहद सक्रिय हो गई है और अब आकर्षण का केन्द्र बने रहने के लिए मुद्दे उछाल रही है। वह अपनी स्वयं की सरकार के संचालन के विविध पहलुओं को लेकर सार्वजनिक मीटिंग्स कर रही हैं। वह प्रशासनिक संचालन के विभिन्न स्तरों पर हुईं गंभीर त्रुटियों को स्वीकार रही हैं। इन गंभीर त्रुटियों के लिए बनर्जी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का नाम लेते हुए उन्हें जिम्मेदार माना है। उन्होंने साल्टलेक के विधायक सुजीत बोस पर बाहर के लोगों को लाने और सरकारी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर स्टाल्स लगवाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कई गंभीर गलतियों के लिए कई सीनियर अधिकारियों को नामतः जिम्मेदार ठहराया है और उनमें से कुछ की जांच व तबादले करने के लिए कहा है।

ममता बनर्जी ने इतने कड़े शब्दों में निंदा की कि कई लोगों को तो लगा कि शहर विकास मंत्री और कलकत्ता के मेयर फिराद हाकिम तुरंत इस्तीफा दे देंगे। जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री तृणमूल नगर निगम की विफलता दर आगबबूला हो रही थी वहां हाकिम भी मौजूद थे।

लेकिन इस आलोचना के पीछे यह स्वीकारोक्ति थी कि शहरी क्षेत्र में तृणमूल पार्टी भाजपा से काफी पिछड़ गई है। कलकत्ता नगर निगम के सभी वॉर्डों में भाजपा आगे रही है।

कलकत्ता उत्तर की सीट से सुदीप बंदोपाध्याय को जीतने में कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से वोटिंग की ताकत मिली थी। अन्यथा सुदीप उनके प्रतिद्वन्द्वी भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय से उत्तरी कोलकाता निर्वाचन क्षेत्र में काफी पीछे चल रहे थे। इन रूझानों को देखते हुए ममता बनर्जी के लिए यह चिन्ता का विषय है कि निकटवर्ती भविष्य में क्या स्थिति होगी।

विशेषज्ञों का कहना है, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो कलकत्ता से ही सारे बदलाव पूरे बंगाल में होते हैं। ऐसा लम्बे समय तक वामपंथी शासन के दौरान हुआ था और यह रूझान कलकत्ता में देखा गया है जहां पर तृणमूल की शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ कमजोर होती दिख रही है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908